THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Telecom Advisory Committee (TAC) for Mumbai was reconstituted in December, 1997 shortly after the expiry of its terms on 30.11.1997.

(d) Does not arise.

ओ॰एफ॰सी॰प्रणाली युक्त टेलीफोन एक्सचेंज

2937. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रायगढ़ जिले में उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां आप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली युक्त टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया गया है तथा इसे कब से चालू किया गया है,

(ख) जिले के कितने स्थानों को इस प्रणाली के साथ जोड़ा गया है;

(ग) क्या इस प्रणाली द्वारा जशपुर नगर को गुमला (बिहार) के साथ जोड़ने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में स्वीकृति देने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ):

(क) स्थानों के नाम	जब से कार्यरत है
रायगढ़	जुलाई, 97
गढ़घोण्डा	अप्रैल, 98
फाथलगांव	अप्रैल, 98
कुकरी	जून, 98
धर्मजयगढ़	अप्रैल, 98

(ख) पांच

(ग) जी नहीं

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन लगाया जाना

2938. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन लगाने से संबंधित नीति को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के अनुसार अपनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन लगाने संबंधी आरंभ कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य किस तिथि को आरंभ किया गया था तथा मार्च, 1997-98 के अंत तक कुल कितने गांवों में टेलीफोन कार्य कर रहे थे और वर्ष 1998-99 के दौरान कितने गांवों में टेलीफोन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाओं का प्रावधान एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में प्रत्येक गांव में कम से कम एक सार्वजनिक टेलीफोन के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। यह ग्रामीण-क्षेत्रों में टेलीफोनों के प्रावधान के अतिरिक्त है। सरकार द्वारा निम्न उपायों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन प्रदान करने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है:—

(1) टेलीफोन लाइने प्रदान करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज खोलना।

(2) देश के सभी गांवों को बुनियादी टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मांग न होने पर भी आम जनता के प्रयोग हेतु प्रत्येक गांव में कम से कम एक सार्वजनिक टेलीफोन लगाना।

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 से काफी पहले से टेलीफोन काम कर रहे थे। इसलिए इस काम को शुरू करने की कोई तारीख नहीं दी जा सकती। तथापि, 31.3.1998 तक कुल 3,10,687 गांवों में कम से कम एक सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। वर्ष 1998-99 के दौरान 45,000 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

Population Served by PCOs

2939. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of persons a PCO serves presently, state-wise;

(b) whether there are any special steps contemplated for improving this ratio in North-East Region; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) Number of estimated urban population served by each PCO is given in the statement (*See below*)

(b) Yes, Sir.

(c) The target of 1000 PCOs has been fixed for N.E. Circle during the year

Statement

P.C.O./Population Ratio as on 31-05-1998

S. No.	Name of Circle/ District	PCO/ Population (Urban) Ratio
1.	A & N	1/804
2.	Andhra Pradesh	1/704
3.	Assam	1/686
4.	Bihar	1/1079
5.	Gujarat	1/532
6.	Haryana	1/635
7.	Himachal Pradesh	1/165
8.	J & K	1/796
9.	Karnataka	1/605
10.	Kerala	1/400
11.	M.P.	1/716
12.	Maharashtra	1/657
13.	North-Eastern	1/662
14.	Orissa	1/394
15.	Punjab	1/291
16.	Rajasthan	1/614
17.	Tamil Nadu	1/644
18.	Uttar Pradesh (Eastern & Western)	1/863
19.	West Bengal	1/1220
20.	Mumbai	1/260
21.	Calcutta	1/712
22.	Delhi	1/303
23.	Chennai	1/202
	TOTAL	1/558

रेलवे स्टेशनों पर डाक/उपडाकघर

2940. **श्री चीमनभाई हरिभाई शुक्ला:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नए डाक/उप-डाकघर और रेलवे स्टेशनों पर ब्रांच डाकघरों को खोलने की कोई नीति तैयार की है और लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजकोट के रैया मार्ग क्षेत्र में एक नया डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या वडोदरा, अजमेर, मुंबई भावनगर, रतलाम और राजकोट मंडलों के मुख्य रेलवे स्टेशनों पर ब्रांच डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस संबंध में किसी सांसद अथवा परामर्श समिति के सदस्य से इस प्रस्ताव सहित कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) सरकार द्वारा रेलवे स्टेशनों पर डाकघर खोलने को कोई नीति नहीं बनाई गई है।

(ख) रैया रोड में दिनांक 28.2.97 को एक डाकघर खोला गया था, परंतु रैया रोड क्षेत्र में उपयुक्त भवन उपलब्ध न होने के कारण यह डाकघर कालावाड रोड डाकघर परिसर में कार्य कर रहा है।

(ग) बडोदरा, अजमेर, मुंबई, भावनगर और राजकोट डिवीजनों के अंतर्गत मुख्य रेलवे स्टेशनों पर शाखा डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रतलाम आर०एस० रोड तथा रतलाम रेलवे कालोनी डाकघर पहले ही रतलाम डिवीजन में कार्य कर रहे हैं।

(घ) मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, गुजरात सर्किल, अहमदाबाद के साथ दिनांक 17.11.97 को हुई बैठक के दौरान रैया रोड, राजकोट में डाकघर खोलने के लिए श्री बल्लभभाई कठारिया, सांसद, राजकोट से एक पत्र / अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ङ) जैसा कि उपर्युक्त (ख) में उल्लेख किया गया है, रैया रोड डाकघर दिनांक 28.2.97 को पहले ही खोल दिया है।

British Telecom's Hidden Agenda on South Asian Hub

2941 SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state: